RAJYA SABHA

Friday, the 7th September, 1990/the 16th Bhadra, 1912 (Saka)

The House met at eleven of the clock, **MR. CHAIRMAN** in the Chair.

MR. CHAIRMAN : Question No. 421. (*Interruption*).

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY (Uttar Pradesh) : Sir, question No. 420 first.

श्री सभापति : आपका सवाल हमेशा हंगामा हो जाता है।

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY : I thought the Prime Minister has come, so he would make a statement on Bofors, on 420. (*Interruptions*).

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry) : He will make statements only outside Parliament, not inside.

THE PRIME MINISTER (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH) : Sir, it is very appropriate that question No. 420 is being asked by Mr. Subramanian Swamy.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY : And, of the Prime Minister of India. And it should be addressed to Mr. V. P. Singh. Then only it will be complete.

उड़ीसा में समेकित बाल विकास योजना का क्रियान्वयन

*421 **श्री जगदीश जानी** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कितनी समेकित बाल विकास योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं;

(ख) क्या सरकार ने 1990-91 वर्ष के लिये कुछ नई समेकित बाल विकास योजनाओं की स्वीकृति दे दी है;

(ग) यदि हां, तो उड़ीसा में इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है;

(घ) क्या उड़ीसा में इस योजना को क्रियान्वित करने के लिये विश्व बैंक की सहायता उपलब्ध कराये जाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्रालय में स्त्री एवं बाल विकास विभाग में उपमंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) उड़ीसा में, 1989-90 तक कुल केन्द्रीय प्रायोजित समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) परियोजनाओं की संख्या 134 है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) उड़ीसा और आन्ध्रप्रदेश राज्यों में बहुराज्यीय आई.सी.डी.एस. परियोजना के परियोजना प्रस्तावों के लिए धनराशि उपलब्ध कराने के लिए वाशिंगटन में विश्व बैंक के प्रतिनिधियों के साथ 11 मई से 18 मई 1990 को वार्ता की गई थी। उड़ीसा के 191 विकास खण्ड इन प्रस्तावों के अन्तर्गत लाये जायेंगे। अभी तक भारत सरकार द्वारा इस परियोजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

श्री जगदीश जानी : सभापति महोदय, 1990-91 के मुख्य वर्ष में उड़ीसा के लिए कोई नया आई.सी.डी.एस. प्रोजेक्ट मंजूर न करने का क्या कारण है? अगर वर्ल्ड बैंक से फण्ड मिल जायेगा तो उड़ीसा को और कितना मिलेगा?

श्रीमती उषा सिंह : उड़ीसा पिछड़े राज्यों में आता है। सात राज्यों का चयन किया गया है। इसलिए वर्ल्ड बैंक के तहत जो योजनाएं हैं उनमें विशेष घटक शामिल किये गये हैं। उड़ीसा को प्राथमिकता देने के आधार पर वर्ल्ड बैंक की योजना ली गयी है। उड़ीसा राज्य के लिए 172.43 करोड़ की लागत की परियोजना की सिफारिश की गयी है।

श्री जगदीश जानी : सभापति महोदय, क्या मंत्री महोदया को यह बात पता है कि उड़ीसा में आदिवासी एरियाज में आई.सी.डी.एस. ज्यादा शुरू नहीं की गयी है। अगर नहीं की गयी है तो वर्ल्ड बैंक द्वारा 1991

वर्ष में जो आई. सी. डी. एस. शुरू की जायेंगी उनमें उड़ीसा में कुल कितनी होंगी और आदिवासी एरियाज में कितनी होंगी?

श्रीमती उषा सिंह : सभापति महोदय, अभी तक की गयी 134 में सबसे ज्यादा प्राथमिकता आदिवासी क्षेत्रों को दी गयी है। हमने 1975 में योजना भी आदिवासी क्षेत्रों से शुरू की। आज उनकी संख्या 82 है आदिवासी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में 48 है। इसलिए आदिवासी क्षेत्रों की संख्या ज्यादा ही है।

MR. CHAIRMAN : Yes, Mr. Lenka.

SHRI KAHNU CHARAN LENKA : Sir, the ICDS is a comprehensive scheme of child development and child welfare and its purpose is to combat malnutrition and to ensure health to children in the crucial first six years. In the present package of the ICDS projects, there is no scheme, there is no provision, for the construction of Anganwadi centres, for the construction of quarters for the staff. You may be aware, Sir, that in Orissa, the ICDS projects are run exclusively by ladies, ...

MR. CHAIRMAN : Everybody understands that. You put your question.

SHRI KAHNU CHARAN LExNKA : .. .and if there is no provision for the construction of quarters, how can they work ? I would like *to* know from the honourbale Minister whether, in the present World Bank's scheme, there is any provision for the construction of buildings for the Anganwadi workers and for the supervisors and for those who are working in the rural areas and, if there is no provision, whether the Government will consider providing funds for the construction of quarters for workers in the rural areas.

श्रीमती उषा सिंह : सभापति महोदय, कार्यरत सभी महिलाएं स्थानीय होती हैं अतः आवास का प्रश्न नहीं है परन्तु सेन्टर की पूर्व में ये सुविधाएं नहीं थीं। अभी दी गयी हैं। इसलिए वर्ल्ड बैंक कार्यक्रम उड़ीसा में दिया गया है जिसमें विशेष कम्पोनेंट में, भवन निर्माण की भी व्यवस्था की गयी है ।

MR. CHAIRMAN : Yes, Mr. Basant Kumar Das.

SHRI KAHNU CHARAN LENKA : Sir, she has not answered my question.

श्री सभापति : पहले नहीं था, अब इसके लिए इंतजाम किया गया है।
That is all. She has given a full answer to your question. Yes, Mr. Das.

SHRI BASANT KUMAR DAS : Sir, I would like to know from the honourable Minister how many Anganwadis were functioning in the year 1987-88 in Kalahandi district and how many are functioning at present and whether the Government proposes to increase the number of the Anganwadi centres in the near future in Kalahandi district.

I would also like to know from the honourable Minister whether the food materials supplied to these centres are from any charitable institutions or whether the expenses for these materials are met from the Government funds. In this connection, I would further like to know who the transport agent for Kalahandi district is and whether the Government has received any complaint regarding shortages in every bag of wheat and dal supplied by the agents and whether the Government has received any complaint regarding the substandard foodstuffs supplied by the agents which are not fit for human consumption. This is one thing. Then, Sir .....

MR. CHAIRMAN : How many questions are you asking ? You have been permitted to put one supplementary only. How many supplementaries do you want to put ? You are allowed only one supplementary. You have already put five supplementaries.

SHRI BASANT KUMAR DAS : What is the scale of salary fixed for the Anganwadi workers ? Is it sufficient to meet the cost of collecting, cooking food and cleaning the utensils ? What does the Government think about improving the situation in Kalahandi ?

MR. CHAIRMAN : How many more questions ? You are permitted only one supplementary. Now I have to stop you after one supplementary and nothing more.

श्रीमती उषा सिंह : सभापति महोदय, उड़ीसा में ब्लाकों की संख्या 314 है, जिसमें

मैंने पहले सदन में बताया कि 134 पहले लिये गये, 191 लिये जा रहे हैं। जो डिस्ट्रिक्ट्स अभी लिये जाएंगे, उनके चयन का निर्णय चार सितम्बर को . . . (*व्यवधान*) बोर्ड आफ डाइरेक्टरस की बैठक में विश्व बैंक ने उन्हें लेने का निर्णय किया है। भारत सरकार के साथ समझौता होना बाकी है।

श्री सभापति : इनका प्रश्न कालाहांडी डिसिट्रक्ट के बारे में है। अब अगर कालाहांडी जिले के बारे में आपके पास सूचना नहीं है, तो आप समय मांग लीजिए।

श्रीमती उषा सिंह : मैं यह सूचना सदन के पटल पर दे दूंगी ।

श्री राम विलास पासवान : महोदय, उस संबंध में 583 आंगनवाड़ी योजनाएं चल रही हैं और उसमें दस ब्लाक्स सम्मिलित हैं।

श्री सभापति : इनका प्रश्न सिर्फ कालाहांडी जिले के बारे में है।

श्री राम विलास पासवान : हां, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में - एक डिस्ट्रिक्ट में आंगनवाड़ी जो होती है, वह एक हजार के ऊपर एक होती है । तो टोटल आंगनवाड़ी की जो योजनाएं चल रही हैं, वह 583 हैं और उसमें दस ब्लाक्स सम्मिलित हैं, क्योंकि सब ब्लाक्स को हम नहीं लेते हैं। उसके लिए चयन किया जाता है। उसमें दस ब्लाक्स शामिल हैं।

SHRI BASANT KUMAR DAS : My question was : "How many centres were there in 1987-88 and how many centres were there in 1989-90 ? According to my information, there were more number of Anganwadi centres in 1987-88 and presently there are less number of Anganwadi centres. Instead of increasing, the number

श्री राम विलास पासवान : यह सूचना 30 जून, 1990 तक की है।

श्री कमल मोरारका : सेंटर कम हो गये हैं।

has decreased.

श्री राम विलास पासवान : उस संबंध में तो मैं जानकारी हासिल करूंगा। मैंने कहा कि 30 जून, 1990 की जो स्थिति है, वह मैंने बता दी है । यदि माननीय सदस्य कोई सूचना दे रहे हैं, तो उसको हम इकट्ठा कर लेंगे।

SHRI BASANT KUMAR DAS : Another question was about the salary fixed for the Anganwadi workers and whether the Government feels that it is adequate for collecting and cooking food and cleaning the utensils.

श्री राम विलास पासवान : सर, जहां तक आंगवाड़ी के वर्कर्ज और हैल्पर्ज की सैलरी का सवाल, है तो जो संस्था बनाई गई है, उसमें सैलरी का फिक्सेशन नहीं था। उसमें सिर्फ इतना ही था कि वालंटरी आर्गेनाइजेशन के रूप में काम करेंगे और उसके लिए 275 से 325 रुपये तक और 225 से 275 रुपये तक का रखा गया था । जो मैट्रिक से नीचे थे, उनका 225 से 275 रुपये था, मैट्रिक से जो ऊपर थे, उनका 275 से 325 रुपये था और हैल्पर्ज के लिए भी 210 रुपये हम उनको देते थे।

लेकिन जहां तक सवाल है सरकारी कर्मचारी का–सरकारी कर्मचारी की उनको मान्यता––उनको सरकारी कर्मचारी के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था, क्योंकि वह पार्ट-टाईम वर्कर्ज के रूप में, हैल्पर्ज के रूप में उनका था और अभी भी सरकार उनको हैल्पर्ज और वर्कर्ज के रूप में ही चाहती है।

जहां तक उनके वेतन या पैसे का सवाल है, मंहगाई को देखते हुए, पैसा कम है, उसमें कोई दो मत नहीं है । सरकार इसके उपर विचार कर रही है ।

श्री सभापति : सामान अच्छा नहीं मिलता, सब-स्टेण्डर्ड होता है।

श्री राम विलास पासवान : उसके ऊपर जहां कहीं से शिकायत आ रही है, हम कार्यवाही कर रहे हैं। यदि माननीय सदस्य किसी सेंटर का बतायें तो उसके ऊपर कार्यवाही करेंगे ।

**422[The question (Shri Ramdas Agarwal) was absent. For answer vide col.* 33-34 infra]

Plight of working Children

*423. SHRI MAHENDRA PRASAD :
SHRI MURLIDHAR CHANDRA KANT BHANDARE : Will the Minister of WELFARE be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a UNICEF report, entitled 'the Invisible Child" as referred to in a news-item captioned, 'Plight of Working Children' which appeared in the 'National Herald' of 14th June, 1990 depicting the conditions of working and other poor children in the capital and in other urban areas in the country; and

(b) if so, what action Government propose to take in this regard with a view to ameliorate their plight ?

THE MINISTER OF LABOUR AND WELFARE (SHRI RAM VILAS PASWAN) : (a) Yes, Sir.

(b) A statement is laid on the Table of the House. *(See* below)

Statement

The report published in National Herald of 14-6-1990 on 'plight of working children' refers to a UNICEF report entitled 'The Invisible Child'. In this report of UNICEF, the plight of poor children in Delhi has been described. The slum dwelling child-, ren's problems regarding shelter, water supply, pollution, malnutrition, health, education, disability etc. have been men- tioned.

2. This problem is essentially because of poverty and a number of programmes by a number of government departments have been undertaken in this direction. For example,

(a) Urban Basic Services . . . By Ministry of Urban Development

(b) Delhi Development Authority—Slum Wing programmes . . . . By Ministry of Urban Development.

(c) Health and Education Programmes . By Delhi Administration,

(d) Programmes for the welfare of children in need of care and protection. . . By Ministry of Welfare.

(e) programme of prevention and control of Juvenile social mal-adjustment.. By Ministry of Welfare.

3. As per the National Policy of Children adopted in 1974, children are assets of the Nation and under this policy, Government tries, to the extent possible, to have programmes for integrated development of children. Under National Child Labour Policy of 1987, regulations and welfare schemes for child labour have been provided for.

The Question was actually asked on the floor of the House by Shri Murlidhar Chandrakant Bhandare.